नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में

मूल क्षेत्राधिकार

दिनांकः नैनीतालः 25जी जुलाई, 2018

2018 का दूसरा जमानत आवेदन संख्या 40

जमानत आवेदन पर आदेशः

अशोक चौहान,

पुत्र श्री सतवीर सिंह,

निवासी गांव लूम्ब,

पी.एस. चपरोली,

जिला बागपत। ..... प्रार्थी

बनाम

उत्तराखंड राज्य.....विपक्षी

2017 की एफआईआर संख्या 27 से उत्पन्न, एनडीपीएस अधिनियम की धारा –8, 20 के तहत पीएस मोरी, जिला उत्तरकाशी में दर्ज किया गया है।

माननीय वी.के. बिष्ट, जे.

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा और उत्तराखंड राज्य के लिए श्री एस.एस अधिकारी, ए.जी.ए।

2. जिला उत्तरकाशी के पीएस मोरी में दर्ज एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा–8, 20 के तहत 2017 की एफआईआर संख्या 27 के संबंध में जेल में बंद प्रार्थी अशोक चौहान ने जमानत पर रिहा करने की मांग की है।

3. दिनांक 03.12.2017 को, प्रार्थी और श्री पुष्पेंद्र के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आक्षेप लगाया गया कि, दोनों अभियुक्तों को मोरी बाजार से आते समय पकड़ा गया था और उनके द्वारा लटकाए गए बैगों की तलाशी के दौरान प्रार्थी के कब्जे से 2.50 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी और सह–अभियुक्त श्री पुष्पेंद्र के कब्जे से 2.350 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी को गिरफ्तार करते समय, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 और धारा 52 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी की गिरफ्तारी करने से पहले, संबंधित अधिकारी ने प्रार्थी को राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने के अपने कानूनी अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया है। इसके अलावा, प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में कथित वसूली नहीं की गई है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलील के समर्थन में, **(2011) 1 एससीसी 609 के पैराग्राफ 29 और 32** पर बल दिया जो इस प्रकार से निम्नलिखित हैं:–

> "29. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा दृढ़ मत है कि एनडीपीएस **अधिनियम की धारा 50 (1)** के तहत जिस उद्देश्य के साथ सुरक्षा उपाय के माध्यम से अधिकार दिया गया है, वह संदिग्ध को प्रदान किया गया है, अर्थात शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए और कानून प्रवर्तन द्वारा झूठे मामले लगाने या थोपने के आरोपों को कम करने के लिए इस प्रावधान का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए तथा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जानी चाहिए। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जहां तक एनडीपीएस अधिनियम के दायित्व का संबंध है, यह अनिवार्य है और इसके सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। प्रावधान का पालन करने में विफलता एजेंसियों की वसूली को प्रभावित करेगी, अधिकार प्राप्त अधिकारी की ओर से यह अनिवार्य होगा कि वह उस व्यक्ति को उप–धारा (1) धारा 50 के तहत अधिकृत अधिकारी होने के अपने अधिकार से अवगत कराए और

दोषसिद्धि को दूषित करे यदि इसे केवल आरोपी के व्यक्ति से अवैध वस्तु की बरामदगी के आधार पर दर्ज किया जाता है। इसके बाद, संदिग्ध उक्त प्रावधान के तहत उसे प्रदान किए गए अधिकार का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकता है या नहीं भी कर सकता है।

32. हम यह भी महसूस करते हैं कि यद्यपि धारा 50 अधिकार प्राप्त अधिकारी को ऐसे व्यक्ति (संदिग्ध) को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने का विकल्प देती है, लेकिन पूरी कार्यवाही को प्रामाणिकता, पारदर्शिता और साख प्रदान करने के लिए, पहली बार में, संदिग्ध को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसे किसी भी अन्य अधिकारी की तुलना में आम आदमी का अधिक विश्वास प्राप्त है। यह न केवल तलाशी कार्यवाही को वैधता प्रदान करेगा, बल्कि यह अभियोजन पक्ष को भी मजबूत कर सकता है''।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा और इस न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि आवेदक किसी भी तरह से गवाहों/मुकदमे को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आधारित सबूतों के आधार पर, आवेदक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से बरामद कथित प्रतिबंधित पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। उन्होंने कहा कि पुलिस पार्टी के लिए आवेदक को गलत तरीके से फंसाने और आवेदक को फंसाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थ खरीदने में बड़ी राशि का निवेश करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिसकर्मियों ने स्वतंत्र गवाह को लाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया और उसके बाद ही सर्कल अधिकारी के समक्ष तलाशी ली गई जो राजपत्रित अधिकारी हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक की गिरफ्तारी एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून के अनुसार अन्य आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी की गई हैं।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **वामन नरायन घिया बनाम राजस्थान राज्य (2002) 2 एससीसी 281** में सूचित के मामले में जमानत शब्द पर चर्चा की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि जमानत याचिका पर विचार करते समय साक्ष्यों की विस्तृत चर्चा और गुण–दोष के विस्तृत प्रलेखन से बचना चाहिए। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 6, 7, 8 और 11 को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा हैः –

> **6**. सीआरपीसी में ''जमानत'' एक अपरिभाषित शब्द बना हुआ है। कहीं और इस शब्द को वैधानिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। अवधारणात्मक रूप से, इसे राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ स्वतंत्रता के दावे के अधिकार के रूप में समझा जाता है। 1948 की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा के बाद से, जिसमें भारतीय एक हस्ताक्षरकर्ता है, जमानत की अवधारणा को मानवाधिकारों के दायरे में जगह मिली है। शब्दकोष का अर्थ 'जमानत' एक कैदी की रिहाई के लिए उसकी उपस्थिति के लिए सुरक्षा को दर्शाता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यह शब्द एक पुरानी फ्रांसीसी क्रिया 'बेलर' से लिया गया है जिसका अर्थ है ''देना'' या ''वितरित करना'', हालांकि एक और दृष्टिकोण यह है कि इसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द ''बैउलरे'' से है, जिसका अर्थ है ''बोझ उठाना''। जमानत एक सशर्त स्वतंत्रता है। स्ट्रोड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी (4वां संस्करण 1971) कुछ अन्य विवरण बताता है, जिसमें कहा गया है किः–
>
> **''**... जब किसी व्यक्ति को गुंडागर्दी के लिए लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, तो गुंडागर्दी का संदेह, गुंडागर्दी का संकेत मिलता है, या ऐसा कोई मामला होता है, ताकि वह अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो और, कानून द्वारा जमानती होने के नाते, उन लोगों को जमानत दाखिल करता है जिनके पास उसे जमानत देने का अधिकार है, जो जमानत उसके लिए राजा के उपयोग के लिए एक निश्चित राशि, या शरीर के लिए निकाय के रूप में बाध्य हैं, कि वह अगले सत्रों में लक्ष्य वितरण के न्यायाधीशों के समक्ष पेश होगा, आदि। फिर इन जमानतदारों के

बंधनों पर, जैसा कि पूर्वोक्त है, उसे जमानत दे दी जाती है – अर्थात, उसकी उपस्थिति के लिए नियत दिन तक स्वतंत्रता निर्धारित की जाती है।

इस प्रकार जमानत को एक तंत्र के रूप में माना जा सकता है जिसके तहत राज्य समुदाय को कैदियों की उपस्थिति को सुरक्षित करने के कार्य को हस्तांतरित करता है, और साथ ही न्याय के प्रशासन में समुदाय की भागीदारी शामिल है।

7. व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक है और इसे केवल कानून द्वारा स्वीकृत कुछ प्रक्रिया द्वारा सीमित किया जा सकता है। एक नागरिक की स्वतंत्रता निस्संदेह महत्वपूर्ण है लेकिन यह समुदाय की सुरक्षा के साथ संतुलन बनाना है। अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस के जांच के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की जांच करने के पुलिस के अधिकार के साथ न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। इसे दो परस्पर विरोधी मांगों को आपस में जोड़ना होगा, अर्थात् एक ओर अपराध करने वाले व्यक्ति के दुस्साहसों के संपर्क में आने के खतरों से बचने के लिए समाज की आवश्यकताएंय और दूसरी ओर, आपराधिक न्यायशास्त्र की मूलभूत तोप, अर्थात, दोषी पाए जाने तक किसी अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा। स्वतंत्रता स्वस्थ संयम के अनुपात में मौजूद है, दूसरों पर हमसे दूर रहने के लिए जितना अधिक संयम है, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता हमारे पास है।

8. जमानत का कानून, कानून की किसी भी अन्य शाखा की तरह, अपना दर्शन है, और न्याय के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जमानत की अवधारणा एक ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस शक्ति के बीच संघर्ष से उभरती है, जिस पर कथित रूप से अपराध करने का आरोप है, और कथित अपराधी के पक्ष में निर्दोषता की धारणा है। एक अभियुक्त को उसके अपराध की धारणा पर दंडित करने के उद्देश्य से हिरासत में नहीं लिया जाता है।

11. जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, सबूतों की विस्तृत चर्चा और गुण–दोष के विस्तृत प्रलेखन से बचना चाहिए। यह आवश्यकता इस वांछनीयता से उपजी है कि किसी भी पक्ष को यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि

उसके मामले को पूर्व–निर्धारित किया गया है। प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व पर केवल विचार किया जाना है। गुणों के विस्तृत विश्लेषण या संपूर्ण अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है। जहां अपराध गंभीर प्रकृति का है, जमानत देने के प्रश्न पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, साक्ष्य के चरित्र और अन्य लोगों के बीच जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में जमानत देने के लिए कतिपय मानदण्ड निर्धारित किए हैं। इस तरह के दो निर्णयों के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां उद्धृत किए गए हैं।

(i) कंवर सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2012) 12 एससीसी 180 के मामले में निर्णय के पैरा संख्या 10 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है कि –

10. ''इस प्रकार, संहिता की धारा 439 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। लेकिन, जमानत देते समय, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय अन्य न्यायालयों के समान विचारों से निर्देशित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराध की गंभीरता, साक्ष्य का चरित्र, पीड़ित और गवाहों के संदर्भ में अभियुक्त की स्थिति और स्थिति, अभियुक्त के न्याय से भागने और अपराध दोहराने की संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और न्याय के मार्ग में बाधा डालने की संभावना और ऐसे अन्य आधारों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। प्रत्येक आपराधिक मामला अपना अजीब तथ्यात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और इसलिए, किसी विशेष मामले के लिए विशिष्ट कुछ आधारों को अदालत द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है। अदालत को केवल यह राय देनी है कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत को पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच नहीं करनी चाहिए और उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सबूतों के इस तरह के आकलन और समय से पहले टिप्पणियों से आरोपी निष्पक्ष सुनवाई से वंचित होने की संभावना है।

(ii) **राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य (2002) 3 एससीसी 598 के मामले में निर्णय के पैराग्राफ संख्या 3 और 4 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा हैः–**

"**3.** जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है– लेकिन, हालांकि, इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने की आवश्यकता है, न कि निश्चित रूप से। किसी ठोस कारण से जमानत के लिए आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। हालांकि, यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत का अनुदान अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करता है और तथ्य, हालांकि, हमेशा अलग–अलग मामले में भिन्न होते हैं। हालांकि, समाज में अभियुक्त की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह जमानत देने के मामले में अपने आप में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है और इसे हमेशा जमानत देने के लिए आवश्यक अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अपराध की प्रकृति जमानत देने के लिए बुनियादी विचारों में से एक है– अपराध जितना जघन्य है, उतना ही अधिक मौका है"।

हालांकि, जमानत की अस्वीकृति मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करती है।

4. उपर्युक्त के अलावा, कुछ अन्य विचार जिन्हें प्रासंगिक विचारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इस समय भी ध्यान दिया जा सकता है, हालांकि, वे केवल चित्रात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं, न ही कोई हो सकता है। विचार हैंः

(क) जमानत देते समय न्यायालय को न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा, बल्कि सजा की गंभीरता को भी ध्यान में रखना होगा, अगर आरोप में दोषसिद्धि और आरोपों के समर्थन में सबूत की प्रकृति शामिल है।

(ख) गवाहों के साथ छेड़छाड़ किए जाने या शिकायतकर्ता के लिए खतरा होने की आशंका की तर्कसंगत आशंकाओं पर भी जमानत देने के मामले में न्यायालय के साथ विचार किया जाना चाहिए।

(ग) यद्यपि यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने वाले पूरे साक्ष्य हों, परन्तु आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि हमेशा होनी चाहिए।

(घ) अभियोजन में पक्षपात पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत प्रदान करने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर विचार करना होगा और अभियोजन पक्ष की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाओं में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।

10. इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य, जयपुर बनाम बालचंद/बलिया के मामले में, जैसा कि (1977) 4 एससीसी 308 में सूचित किया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मूल नियम जमानत है न कि जेल।

11. इसलिए, मूल नियम जमानत है न कि जेल के अलावा, जमानत देते समय, विचार किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक अपराध की प्रकृति है

और गवाहों/मुकदमे के आरोपी व्यक्ति द्वारा प्रभावित किए जाने की संभावना।

12. मैंने पक्षों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। मेरा विचार है कि जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला है।

13. जमानत याचिका स्वीकार की जाती है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट इस आदेश में की गई टिप्पणी से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

14. आवेदक को व्यक्तिगत मुचलके को निष्पादित करने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए दो विश्वसनीय और स्थानीय जमानती, प्रत्येक राशि प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

15. इस मामले से इतर, इस न्यायालय का यह भी मत है कि, एन.डी.पी.एस अधिनियम से संबंधित कई मामलों में, प्रथम सूचना रिपोर्ट साइक्लोस्टाइल (विहित प्रारूप में एक ही समान) तरीके से दर्ज की जा रही है। उदाहरण के लिए, गश्त करते समय, पुलिस दल को अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, जो पुलिस दल को देखने के बाद भागने की

कोशिश करता है। पुलिस दल उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लेता है। ज्यादातर मामलों में, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलता है। हालांकि, जमा तलाशी राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाती है, लेकिन फिर भी, लगभग हर मामले में, वह पुलिस अधिकारी होता है। यद्यपि इसका अनुपालन दिखाया जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति में, निर्दोष व्यक्ति को झूठा फसांया जा सकता है? ऐसे में निर्दोष व्यक्ति को फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस पार्टी उस व्यक्ति से उस व्यक्ति का नाम पूछने की जहमत भी नहीं उठाती है, जिससे उसने प्रतिबंधित पदार्थ खरीदा था। लगभग हर मामले में, अभियुक्त व्यक्ति वाहक होते हैं और एफ.आई.आर. और पुलिस कर्मियों के सबूतों के आधार पर, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। आजकल जबकि कैमरे और वीडियो कैमरे आसानी से उपलब्ध हैं और आरोपियों की संलिप्तता दिखाने वाली कथित वसूली की वीडियोग्राफी आसानी से की जा सकती है, जो ज्यादातर मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी होने पर की जा रही है। इस पहलू पर गौर किया जा सकता है। इसलिए, मैं निर्देश देता हूं कि इस आदेश की एक प्रति राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए।

(वी.के. बिष्ट, जे.)

25.07.2018